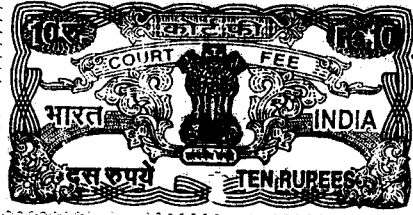
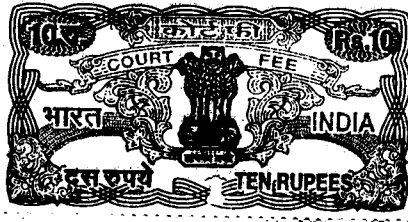


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल न्यायालय केम्प भीपाल म 090



1. सूरजदेवी देवा बालकिशन दास

निगरानी 1714-PBR-15

2. पुरु जीत्तम आठ श्री बालकिशन दास माहेश्वरी

3. राजेश आठ श्री बालकिशनदास माहेश्वरी

तीनों निवासी शोभापुर, तहसील - सोहागपुर

जिला होशंगाबाद म.प्र.

4. नंदलाल आठ स्व० श्री बालकिशन दास माहेश्वरी

निवासी ग्राम शोभापुर, हाल मुकाम गिन्नी कम्पाउण्ड

होशंगाबाद, तहसील व जिला होशंगाबाद म.प्र. ————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती लता बाहेती देवा स्व० श्री विजय कुमार बाहेती

2. छठकेसरी शीरम आठ स्व० श्री विजय कुमार बाहेती

3. शिरिन पुत्री स्व० श्री विजय कुमार बाहेती

तीनों निवासी - अशोक इंकलेव 0301 -ए अपसरा टाकीज

के पास, रायसेन रोड भीपाल म.प्र.

————— उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा 50-090 में राजस्व संहिता.

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के द्वारा पारित आदेशा दिनांक 7.5.2015 जिसका कि प्रकरण क्र. 2-अ/06 अर्थात् वर्ष 2014-2015 मौजा काजलेडी में पारित आदेशा से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित न्यायो एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

(Signature)

श्री संदीप डवे
सिनासक द्वारा
ज दिनांक
4-6-15 को
भीपाल केम्प
में प्रस्तुत।
GJM
24-6-15


(Signature)
26-6-15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1714-पीबीआर/15

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-8-2015	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, सोहागपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-10-2014 के पुनर्विलोकन की अनुमति तहसीलदार, हरदा द्वारा मांगी गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2708-एक/13 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2013 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 756/2014 प्रचलनशील है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30-1-2014 को आदेश पारित कर विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में तहसीलदार को पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाना उचित नहीं है, पुनर्विलोकन की चाही गई अनुमति निरस्त की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;">  (मनोज गोयल) अध्यक्ष </p>